पूरी पीठ

आर.एस. नरूला, बल राज तुली और मुनि लाल वर्मा से पहले जे.जे.

महंत बिक्रम दास,-अपीलकर्ता।

बनाम

वित्तीय आयुक्त, प्रतिवादी।

1971 का पत्र पेटेंट अपील संख्या 65।

19 मार्च 1974.

परिसीमा अधिनियम (1908 का IX) -अनुच्छेद 151 - परिसीमा अधिनियम (1963 का XXXVI) -अनुच्छेद 117 -पंजाब उच्च न्यायालय के पत्र पेटेंट -खंड X -पंजाब उच्च न्यायालय के नियम और आदेश, खंड V, अध्याय एल-ए (ए) -नियम 4 - लेटर्स पेटेंट अपील समय से परे दायर की गई - देरी को माफ करने और समय बढ़ाने की शक्ति - चाहे इसे स्वीकार करने वाली बेंच तक ही सीमित हो - समय बढ़ाने के लिए अपील की सुनवाई करने वाली बेंच का क्षेत्राधिकार - चाहे नियम 4 द्वारा हटा दिया गया हो - लेटर्स पेटेंट अपील को प्राथमिकता देने में देरी - चाहे मोशन बेंच द्वारा इसे स्वीकार करते हुए निहित रूप से माफ कर दिया गया - आदेश 41 नियम 3, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत कुछ आधार पर अपील खारिज की जा सकती है - क्या प्रवेश के बाद उसी आधार पर सुनवाई की जा सकती है - अपील का ज्ञापन आदेश 41 नियम 1 के अनुसार तैयार किया गया - क्या उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए प्रक्रिया के किसी भी नियम का अनुपालन न करने पर खारिज किया जा सकता है - पत्र पेटेंट अपील पेपर-बुक की अपेक्षित तीन अतिरिक्त प्रतियों के साथ नहीं है - चाहे कानून में सक्षम हो - ऐसी अपील मूल रूप से समय से दायर की गई है लेकिन समय से परे अतिरिक्त पुस्तकों के साथ पुनः दाखिल - क्या समय से बाधित के रूप में खारिज किया जा सकता है - अपील हालांकि समय के भीतर दायर की गई लेकिन एक निर्दिष्ट समय के भीतर दोष को दूर करने के लिए वापस कर दी गई - निर्दिष्ट समय की समाप्ति के बाद अपील फिर से दायर की गई

लेकिन उसके बाद के 40 दिन के भीतर और उप रजिस्ट्रार उस पर विचार कर रहा है - पहली बार में निर्दिष्ट समय - क्या इसे बढ़ाया गया माना जाता है।

अभिनिर्धारित किया गया कि जनवरी, 1964 से पहले की अवधि के दौरान, जब परिसीमन अधिनियम, 1908 लागू था, अधिनियम के अनुच्छेद 151 ने पंजाब उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों, खंड V, के अध्याय 1-ए(ए) के नियम 4 को लेटर्स पेटेंट के खंड 27 के तहत उच्च न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति के तहत रास्ता दियाऔ र एक विशेष कानून की स्थिति का आनंद लिया। लेटर्स पेटेंट के क्लॉज एक्स के तहत अपील के लिए सीमा की अवधि उस फैसले की तारीख से 30 दिन थी जिसके खिलाफ अपील की गई थी। हालाँकि, जब 1 जनवरी, 1964 को परिसीमा अधिनियम, 1963 लागू हुआ, तो अनुच्छेद 117 ने परिसीमा अधिनियम, 1908 के अनुच्छेद 151 को प्रतिस्थापित कर दिया। अनुच्छेद 117 पत्र पेटेंट अपील के लिए 30 दिन प्रदान करता है। यदि लेटर्स पेटेंट अपील उस समय के बाहर दायर की गई थी जब लिमिटेशन एक्ट, 1908 लागू था तो केवल स्वीकार करने वाली पीठ ही समय का विस्तार दे सकती थी। यदि ऐसी अपील परिसीमा अधिनियम, 1963 के लागू होने के बाद, यानी 1 जनवरी 1964 को या उसके बाद दायर की जाती है, तो स्वीकार करने वाली पीठ अस्थायी रूप से देरी को माफ करने के सवाल पर विचार कर सकती है, लेकिन अंततः अपील की सुनवाई सभी संबंधित पक्षों को सुनने के बाद, करने वाली पीठ ही होगी। अंततः, सीमा से परे अपील दायर करने के लिए कारण की पर्याप्तता पर विचार करेंगे और अधिनियम की धारा 5 के तहत देरी को माफ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं।

(पैरा 4 और 5)

यह निर्धारित किया गया कि क्या लेटर पेटेंट अपील को प्राथमिकता देने के लिए देरी की माफी की आवश्यकता वाला मामला पंजाब उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों, खंड V के अध्याय एल-ए (ए) के नियम 4 के तहत है या दो सीमा अधिनियमों में से किसी एक की धारा 5 के तहत है, देरी को माफ करते हुए बेंच को यह दर्ज करना होगा कि देरी पर्याप्त और अच्छे कारण के कारण हुई थी। खंडपीठ का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए कि दायर की गई अपील समय से बाधित थी और देरी की माफी वांछित या आवश्यक थी। इसके बाद बेंच देरी को माफ करने के

लिए दिए गए कारणों पर अपना दिमाग लगाएगी और यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि देरी पर्याप्त और अच्छे कारण के कारण हुई है, तो देरी को माफ किया जा सकता है, लेकिन अपील को स्वीकार कर लिया गया, बिना ध्यान दिए कि पीठ को इस तथ्य से अवगत कराया जा रहा है कि उस पर समय की रोक है, इसलिए देरी को माफ करने का कोई असर नहीं होगा। यह प्रतिवादी या उत्तरदाताओं के लिए परिसीमा की दलील उठाने के लिए खुला होगा और अपील की सुनवाई करने वाली पीठ उस आवेदन पर अपना निर्णय दर्ज करेगी।

(पैरा 7)

निर्धारित किया गया कि यद्यपि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XLI के नियम 1 के अनुसार अपील के ज्ञापन को तैयार करने पर आपत्ति प्रारंभिक चरण में ली जानी चाहिए, फिर भी आदेश या संहिता के अन्य प्रावधान या उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियम में कुछ भी नहीं है, जो मोशन बेंच द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद, संहिता के आदेश XLI, नियम 3 के तहत अपील के ज्ञापन को खारिज करने की शक्तियों के प्रयोग पर रोक लगाते हैं। इस शक्ति का प्रयोग अपील की सुनवाई करने वाला न्यायालय बाद के चरण में प्रतिवादी द्वारा की गई आपत्ति पर भी कर सकता है। इसलिए आदेश एक्सएलआई, संहिता के नियम 3 के तहत किसी आधार पर खारिज की जा सकने वाली अपील को उसी आधार पर स्वीकार किए जाने के बाद खारिज किया जा सकता है।

(पैरा 8)

निर्धारित किया गया कि प्रक्रिया के नियम पंजाब उच्च न्यायालय द्वारा नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 122 और 129 या लेटर्स पेटेंट के खंड 27 के तहत उपलब्ध नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाए गए हैं। इसलिए, नियमों में कानून का बल है और अपील दायर करने के लिए पूर्व शर्त या आवश्यक शर्त निर्धारित करने वाले पंजाब उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए किसी भी नियम का अनुपालन न करने पर अपील का ज्ञापन कानून में सक्षम और अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(पैरा 9)

निर्धारित किया गया कि यदि लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत अपील दस्तावेजों की टाइप की गई प्रतियों के तीन सेट दाखिल न करके नियमों के अध्याय 2-सी के नियम 3 के अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं करती है, तो इसे कानून की नजर में कोई अपील नहीं माना जाना चाहिए और उस दिन दायर किया गया नहीं माना जाएगा। इसे केवल उसी दिन दायर किया गया माना जाएगा जब यह नियमों के अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण हो जाएगा और उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा पंजीकरण के लिए अनुमति दे दी जाएगी। एक लेटर्स पेटेंट अपील को उस दिन वैध और उचित रूप से दायर माना जाएगा जब इसे नियमों के नियम 8, अध्याय 2-सी में उल्लिखित दस्तावेजों के तीन सेटों के साथ दायर किया जाएगा। ऐसी अपील यदि मूल रूप से समय के भीतर प्रस्तुत किए जाने पर दस्तावेजों की प्रतियों के तीन सेटों के साथ नहीं होती है, तो समय-बाधित के रूप में खारिज कर दी जाएगी यदि यह इसके लिए निर्धारित सीमा की अवधि की समाप्ति के बाद तीन सेटों के साथ दायर की जाती है, जब तक कि देरी को सीमा अधिनियम की धारा 5, या पंजाब उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों, खंड V के अध्याय एल-ए (ए) के नियम 4, जो भी लागू हो, के तहत माफ नहीं किया जाता है।

(पैरा 15 एवं 16)

यह निर्धारित किया गया कि यदि कोई अपील, जो मूल रूप से समय के भीतर दायर की गई थी, उप रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित समय के भीतर संशोधन और पुनः दाखिल करने के लिए वापस कर दी जाती है, और प्रारंभिक प्रस्तुति के 40 दिनों के भीतर दोबारा दाखिल करने पर उप रजिस्ट्रार द्वारा बिना किसी आपत्ति के उस पर विचार किया जाता है, हालांकि संशोधन और उसे दोबारा भरने के लिए उसके द्वारा दी गई अवधि की समाप्ति के बाद, यह माना जाएगा कि उप रजिस्ट्रार ने उसे दोबारा दाखिल करने के लिए उस तारीख तक का समय बढ़ा दिया है जब उसने इस पर विचार किया था।

(पैरा 11)

1 सितंबर, 1972 को माननीय श्री न्यायमूर्ति आर.एस. नरूला और माननीय श्री न्यायमूर्ति राजेंद्र नाथ मित्तल की खंडपीठ द्वारा मामले से जुड़े कानून के निम्नलिखित सात प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए मामले को पूर्ण पीठ को भेजा गया। पूर्ण पीठ में माननीय श्री न्यायमूर्ति आर.एस. नरूला, माननीय श्री न्यायमूर्ति बाल राज तुली और माननीय श्री न्यायमूर्ति मुनि लाल वर्मा ने संदर्भित कानून के प्रश्नों पर निर्णय लेने के बाद मामले को कानून के अनुसार तय करने के लिए 19 मार्च, 1974 को डिवीजन बेंच को वापस कर दिया।

(1) क्या इस न्यायालय के लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत अपील दायर करने में देरी को माफ करने या समय बढ़ाने की शक्ति अपील स्वीकार करने वाली बेंच तक ही सीमित है; और इस न्यायालय खंड V के नियमों और आदेशों के अध्याय 1-ए (ए) का नियम 4 अपील सुनने वाली बेंच या मोशन बेंच के अलावा किसी अन्य बेंच के समय बढ़ाने के अधिकार क्षेत्र को छीन लेता है? दूसरे शब्दों में, क्या जनार्दन मिश्रा के मामले में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा निर्धारित कानून सही है या मातू राम और अन्य के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा और पहले की डिवीजन बेंच के हरबंस सिंह के मामले में यह न्यायालय द्वारा व्यक्त विचार सही है?

(2) क्या अपील को प्राथमिकता देने में देरी को मोशन बेंच द्वारा सीमा अवधि की समाप्ति के बाद सुनवाई के लिए स्वीकार करके निहित रूप से माफ कर दिया गया माना जाता है?

(3) क्या किसी अपील को उस आधार पर स्वीकार करने के बाद खारिज किया जा सकता है जिस पर सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 3 के तहत इसे खारिज किया जा सकता था?

(4) क्या अपील के ज्ञापन को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 3 में निर्दिष्ट नहीं बल्कि इस न्यायालय द्वारा बनाए गए प्रक्रिया के किसी भी नियम का अनुपालन न करने के आधार पर खारिज किया जा सकता है?

(5) क्या एक लेटर पेटेंट अपील, जिसे संहिता के 41 नियम 3 के तहत खारिज नहीं किया गया है, को समय-बाधित के रूप में खारिज कर दिया जा सकता है और इस आधार पर कि हालांकि यह मूल

रूप से समय के भीतर दायर किया गया था, इसे समय से परे अतिरिक्त पेपर-किताबों के साथ फिर से दाखिल किया गया है ?

(6) रजिस्ट्री द्वारा उस अपील पर विचार करने का क्या प्रभाव पड़ता है जो रिटर्न के समर्थन में अनुमत समय से परे सीमा की अवधि की समाप्ति के बाद फिर से दायर की जाती है, लेकिन रिटर्न के आदेश के चालीस दिनों के भीतर यदि अपील मूल रूप से समय के भीतर दायर की गई थी? और

(7) क्या लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत किसी अपील को केवल इसलिए अधूरा या "कानून की नजर में कोई अपील नहीं" माना जा सकता है, क्योंकि उसके साथ पेपरबुक की अपेक्षित तीन अतिरिक्त प्रतियां नहीं हैं?

27 नवंबर, 1970 को 1966 के सिविल रिट संख्या 1146 में माननीय श्री न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया द्वारा पारित फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत लेटर्स पेटेंट अपील।

सी.एम.4005/1972.

भारतीय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत आवेदन, प्रार्थना करते हुए कि अपील को समय के भीतर माना जाए और यदि कोई देरी हो तो उसे माफ कर दिया जाए और अपील का निर्णय गुण-दोष के आधार पर किया जाए।

अपीलकर्ता के वकील जगन नाथ कौशल, वरिष्ठ वकील अशोक भान।
हरबंस लाल सरीन, वकील एम. एल. सरीन, प्रतिवादियों के वकील।

आदेश

न्यायमूर्ति वर्मा - इस न्यायालय में सिविल रिट याचिका संख्या 1146/1966 दायर की, जिसे 27 नवंबर, 1970 को एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने खारिज कर दिया। उस फैसले के खिलाफ

अपीलकर्ता ने धारा के तहत एक अपील दायर की। 23 दिसंबर 1970 को लेटर्स पेटेंट के 10। डिप्टी रजिस्ट्रार ने कुछ आपत्तियां उठाईं, जिसमें यह भी शामिल था कि उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों के अध्याय 2-सी के नियम 3 के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों की टाइप की गई प्रतियों की तीन बिक्री नहीं की गई थी। वॉल्यूम. वी, और दोषों को दूर करने और एक सप्ताह के भीतर इसे फिर से दाखिल करने के लिए अपीलकर्ता के विद्वान वकील को इसे वापस करने का आदेश दिया। वापसी का आदेश 23 दिसंबर 1970 को पारित किया गया था, लेकिन यह पता लगाना संभव नहीं हो सका कि किस तारीख को विद्वान वकील या उनके क्लर्क ने इसे न्यायालय से वापस ले लिया। हालाँकि, उप रजिस्ट्रार द्वारा बताई गई खामियों को दूर करने के बाद, अपील 30 जनवरी, 1971 को फिर से दायर की गई। उप रजिस्ट्रार द्वारा एक सप्ताह से अधिक की अनुमति के बाद इसे फिर से दाखिल करने पर कोई आपत्ति नहीं की गई: 24 फरवरी को, 1971, अपील को सीमा के प्रश्न पर ध्यान दिए बिना मोशन बेंच द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। 19 अप्रैल, 1972 को, जब अपील डिवीजन बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए आई, तो दयाल सिंह, हरभजन सिंह और हरबंस सिंह, प्रतिवादी प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने आपत्ति उठाई कि यह समय से बाधित है। इसके बाद, अपीलकर्ता ने अपील प्रस्तुत करने में देरी, यदि कोई हो, को माफ करने के लिए सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक आवेदन दायर किया। उक्त आवेदन का दयाल सिंह, हरभजन सिंह और हरबंस सिंह (बाद में प्रतिवादी कहा जाएगा) ने विरोध किया। अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया कि अपील, जब शुरू में 23 दिसंबर, 1970 को प्रस्तुत की गई थी, समय के भीतर थी और अन्यथा भी, यदि अपील को स्वीकार करते समय इसे दोबारा दायर किया गया तो मोशन बेंच को इसकी प्रस्तुति में कोई देरी हुई। , इसे माफ कर दिया गया माना जाएगा। दूसरी ओर, प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि मामले की परिस्थितियों में, अपील को 30 जनवरी, 1971 को प्रस्तुत किया गया माना जाना चाहिए, और चूंकि उस समय उस पर समय की रोक थी, इसलिए यह केवल मोशन बेंच थी। जो, उचित कारण दर्शाए जाने पर, देरी को माफ कर सकता है। इस संबंध में उनके द्वारा उच्च न्यायालय नियमों के अध्याय 1-ए (ए) के नियम 4 पर भरोसा किया गया थाऔर आदेश, वॉल्यूम। वी, और इस न्यायालय के साथ-साथ दिल्ली और लाहौर के उच्च न्यायालयों के कुछ निर्णय। 1 सितंबर, 1972 को अपील पर सुनवाई करते हुए डिवीजन बेंच ने महसूस किया कि कानून के बहुत सारे सार्वजनिक महत्व के और दैनिक घटना वाले प्रश्न शामिल थे, जिनके निर्धारण के लिए एक बड़ी बेंच

की आवश्यकता थी, खासकर क्योंकि विद्वान न्यायाधीशों के बीच मतभेद था। जैसा कि बार में उद्धृत निर्णयों से पता चलता है। नतीजतन, डिवीजन बेंच ने निर्णय के लिए पूर्ण बेंच को भेजे जाने के लिए निम्नलिखित सात प्रश्न तैयार किए:--

(1) क्या इस न्यायालय के लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत अपील दायर करने में देरी को माफ करने या समय बढ़ाने की शक्ति अपील स्वीकार करने वाली बेंच और चैप के नियम 4 तक ही सीमित है। इस न्यायालय के नियमों और आदेशों के 1-ए (ए), वॉल्यूम। वी, अपील सुनने वाली बेंच या मोशन बेंच के अलावा किसी अन्य बेंच का समय बढ़ाने का अधिकार क्षेत्र छीन लेता है? दूसरे शब्दों में, क्या जनार्दन मिश्रा के मामले में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा निर्धारित कानून सही है या मातू राम और अन्य के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा और पहले की डिवीजन बेंच द्वारा व्यक्त की गई राय सही है। हरबंस सिंह के मामले में यह न्यायालय सुदृढ़ है?

(2) क्या अपील को प्राथमिकता देने में देरी को मोशन बेंच द्वारा सीमा अवधि की समाप्ति के बाद सुनवाई के लिए स्वीकार करके निहित रूप से माफ कर दिया गया माना जाता है?

(3) क्या किसी अपील को उस आधार पर स्वीकार किए जाने के बाद खारिज किया जा सकता है जिस पर सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश एक्सएलआई, नियम 3 के तहत इसे खारिज किया जा सकता था ?

(4) क्या अपील के ज्ञापन को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश एक्सएलआई, नियम 3 में निर्दिष्ट नहीं बल्कि इस न्यायालय द्वारा बनाए गए प्रक्रिया के किसी भी नियम का अनुपालन न करने के आधार पर खारिज किया जा सकता है?

(5) क्या एक लेटर्स पेटेंट अपील, जिसे आदेश एक्सएलआई, संहिता के नियम 3 के तहत खारिज नहीं किया गया है, को इस आधार पर समय-बाधित के रूप में खारिज किया जा सकता है कि हालांकि यह मूल रूप से समय के भीतर दायर किया गया था, इसे अतिरिक्त कागज के साथ फिर से दाखिल किया गया है -समय से परे किताबें?

(6) रजिस्ट्री द्वारा उस अपील पर विचार करने का क्या प्रभाव पड़ता है जो रिटर्न के समर्थन में अनुमत समय से परे सीमा की अवधि की समाप्ति के बाद फिर से दायर की जाती है, लेकिन रिटर्न के आदेश के चालीस दिनों के भीतर यदि अपील मूल रूप से दायर की गई थी समय के भीतर?

(7) क्या लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत किसी अपील को केवल इसलिए अधूरा या "कानून की नजर में कोई अपील नहीं" माना जा सकता है क्योंकि इसके साथ पेपर-बुक की अपेक्षित तीन अतिरिक्त प्रतियां नहीं हैं?

तदनुसार, इन मामलों पर निर्णय लेने के लिए इस पूर्ण पीठ का गठन किया गया है।

2. पक्षों के विद्वान वकील द्वारा दी गई दलीलों की सराहना करने और उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर दर्ज करने के लिए, बार में उद्धृत कानून के प्रासंगिक प्रावधानों, यानी, इस न्यायालय के नियमों और आदेशों खंड V (इसके बाद नियमों के रूप में संदर्भित), लेटर्स पेटेंट के प्रासंगिक खंड और भारतीय सीमा अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा। 1908 का क्रमांक 9 (इसके बाद 1908 का अधिनियम क्रमांक 9 कहा जाएगा), साथ ही परिसीमा अधिनियम, 1963 का क्रमांक 36 (इसके बाद 1963 का अधिनियम क्रमांक 36 कहा जाएगा), जो 1 जनवरी 1964 को लागू हुआ। ये प्रावधान इस प्रकार हैं:--

नियमों के अध्याय 1-ए (ए) का नियम 4:

"लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत अपील के किसी भी ज्ञापन पर विचार नहीं किया जाएगा यदि अपील किए गए निर्णय की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद प्रस्तुत किया जाता है, जब तक कि स्वीकार करने वाली पीठ अपने विवेक से, दिखाए गए अच्छे कारण के लिए आगे का समय नहीं देती है। प्रस्तुतीकरण। अपील के ऐसे ज्ञापन के साथ जिस फैसले की अपील की गई है उसकी प्रति संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपील के ज्ञापन के लिए खंड 10 के तहत एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, जिसमें इस आशय की घोषणा होनी चाहिए कि जिस न्यायाधीश ने फैसला सुनाया है उन्होंने प्रमाणित किया है कि मामला अपील के लिए उपयुक्त है।

टाई जज से प्रमाण पत्र प्राप्त करने में लगने वाला समय (आवेदन की तारीख और जज द्वारा आदेश पारित करने की तारीख सहित) परिसीमा की अवधि की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। भारतीय सीमा अधिनियम की धारा 12 लेटर्स पेटेंट के तहत अपील को नियंत्रित करती है और ऐसे मामले में अपीलकर्ता उस फैसले की एक प्रति प्राप्त करने के लिए "चूना अपेक्षित" को बाहर करने का हकदार है जिसके खिलाफ अपील की गई है (चाहे ऐसी प्रति दायर की गई हो या नहीं) भले ही न्यायालय के नियमों के तहत अपील के ज्ञापन के साथ निर्णय की कोई प्रति दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।"

नियम 5(1) उप-रजिस्ट्रार आदेश XLI,नियम 3,सिविल प्रक्रिया संहिता में निर्दिष्ट कारण के लिए अपील के किसी भी ज्ञापन को एक बार में 10 दिनों से अधिक नहीं और कुल मिलाकर 40 दिनों के भीतर संशोधन और पुनः दाखिल करने के लिए वापस कर सकता है। यदि उप-नियम (1) के तहत उप रजिस्ट्रार द्वारा दिए गए समय के भीतर अपील के ज्ञापन में संशोधन नहीं किया जाता है, तो इसे न्यायालय के समक्ष आदेशों के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

(2) यदि उप-नियम (1) के तहत उप रजिस्ट्रार द्वारा अनुमत समय के भीतर अपील के ज्ञापन में संशोधन नहीं किया जाता है , तो इसे न्यायालय के समक्ष आदेश के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

नियमों के अध्याय 2-सी के नियम 2 और 3:

"2. ऐसी अपीलों में पेपर-बुक (अर्थात लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत) में आमतौर पर शामिल होंगे:--

(ए) अपील का ज्ञापन,

(बी) जिस फैसले की अपील की गई है उसकी एक प्रति;

(सी) निर्णय या अन्य दस्तावेजों की प्रति जो उस न्यायाधीश के समक्ष थे जिनके निर्णय के आधार पर अपील की गई है।

"3. लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत कोई भी अपील उप रजिस्ट्रार को तब तक प्राप्त नहीं होगी जब तक कि उसके साथ निम्नलिखित की तीन टाइप की गई प्रतियां न हों:--

(ए) अपील का ज्ञापन;

(बी) निर्णय से अपील की गई, और

(सी) पेपर-बुक जो उस न्यायाधीश के समक्ष थी जिसके फैसले के आधार पर अपील की गई है।"

खंड 27. और हम यह भी निर्धारित करते हैं कि लाहौर में न्यायिक उच्च न्यायालय के लिए समय-समय पर न्यायालय के अभ्यास को विनियमित करने के लिए नियम और आदेश बनाना और जहां तक संभव हो सके प्रावधानों को अपनाने के उद्देश्य से यह वैध होगा। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का एक अधिनियम, संख्या 5 होने के नाते, काउंसिल में गवर्नर-जनरल द्वारा पारित किया गया, और किसी भी कानून के प्रावधान जो भारत के लिए सक्षम विधायी प्राधिकारी द्वारा बनाए गए हैं या, क्रमशः वसीयतनामा, निर्वसीयत और वैवाहिक क्षेत्राधिकार में सभी कार्यवाहियों के लिए बनाए जा सकते हैं।

खंड 37. और हम आगे निर्धारित और घोषित करते हैं कि हमारे इन लेटर्स पेटेंट के सभी प्रावधान विधान परिषद में गवर्नर-जनरल की विधायी शक्तियों के अधीन हैं, और धारा इकहत्तर के तहत परिषद में गवर्नर-जनरल की भी। भारत सरकार अधिनियम, 1915 और उस विज्ञापन की धारा बहत्तर के तहत आपातकाल के मामलों में गवर्नर-जनरल का भी, और सभी मामलों में इसमें संशोधन और परिवर्तन किया जा सकता है।"

अधिनियम संख्या 1908 का 9

"धारा 29(2)। जहां कोई विशेष या स्थानीय कानून किसी मुकदमे, अपील या आवेदन के लिए पहली अनुसूची द्वारा निर्धारित अवधि से भिन्न सीमा अवधि निर्धारित करता है, धारा 3 के प्रावधान लागू होंगे, जैसे कि इसलिए उस अनुसूची में ऐसी अवधि निर्धारित की गई थी..."

पहली अनुसूची

अपील का विवरण	सीमा की अवधि	जिस अवधि से समय चलना शुरू होता है 1963 का अधिनियम क्रमांक 36.
151. अपने मूल क्षेत्राधिकार के प्रयोग में फोर्ट विलियम, मद्रास और बॉम्बे के किसी भी उच्च न्यायालय या पंजाब के उच्च न्यायालय के डिक्री या आदेश से।	बीस दिन	डिक्री या आदेश की तारीख

1963 के अधिनियम संख्या 36 की धारा 29(2) में निहित प्रावधान 1908 के एडीई संख्या 9 की पूर्वोक्त धारा 29(2) में निहित प्रावधान के समान है। 1963 के अधिनियम संख्या 36 के अनुच्छेद 117 इस प्रकार है :–

अपील का विवरण	सीमा की अवधि	जिस अवधि से समय चलना शुरू होता है
117. किसी उच्च न्यायालय की डिक्री या आदेश से उसी	तीस दिन	डिक्री या आदेश की तारीख

न्यायालय को।		

अब मैं उनका उत्तर देने के उद्देश्य से हमारे सामने आए विभिन्न प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ता हूं।

प्रश्न संख्या 1

3. रामेश्वर दास बनाम ऑफिशियल रिसीवर[1], दिल्ली ; हरबंस सिंह बनाम करम चंद[2] ; मातु राम बनाम भारत संघ[3], और इस न्यायालय का एसी असूचित निर्णय, दिनांक 29 अगस्त, 1963। देस राज बनाम प्रशासक[4], नगर पालिका समिति, सोनीपत, में श्री एचएल उत्तरदाताओं के विद्वान वकील सरीन ने तर्क दिया कि मोशन बेंच एकमात्र बेंच थी जो अपील दायर करने में हुई देरी को माफ कर सकती थी, और कोई अन्य बेंच, यहां तक कि अपील की सुनवाई करने वाली बेंच भी, अपील प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने में सक्षम नहीं थी। वहीं दूसरी ओर अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री जेएन कौशल ने इस न्यायालय के 11 जनवरी 1968 के सी. एमएस नंबर 4353 ऑफ 1966 और 415 ऑफ 1967 में एलपीए नंबर 428 ऑफ 1966 (पुंज) के एक असूचित फैसले जनार्दन मिश्रा बनाम पीएन थापर पर भरोसा करते हुए कहा कि अपील की सुनवाई करने वाली पीठ के पास इसे दायर करने में देरी, यदि कोई हो, को माफ करने का अधिकार क्षेत्र है।

4. वर्तमान में यह देखा जाएगा कि श्री सरीन द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, वे मौजूदा मामले पर लागू नहीं होते हैं और वर्तमान मामला जनार्दन मिश्रा के मामले में दर्ज फैसले के अंतर्गत आता है, और श्री कौशल का तर्क ठोस है और मान्य होना चाहिए। सच है, श्री सरीन द्वारा उद्धृत मामलों का फैसला करने वाले विद्वान न्यायाधीशों की आम सहमति यह थी कि मोशन बेंच (नियम 4 में स्वीकार करने वाली बेंच के रूप में संदर्भित) अकेले ही, अच्छे कारण के लिए, लेटर्स पेटेंट अपील

---

[1] एआईआर 1938 लाह 325

[2] 51 पुन एलआर 50 - (एआईआर 1949 पूर्वी पुंज 299)

[3] एआईआर 1967 दिल्ली 58

[4] एलपीए नंबर 266 ऑफ 1960 (पुंज)

प्रस्तुत करने के लिए उक्त नियम द्वारा निर्धारित 30 दिनों की अवधि बढ़ाने के लिए सक्षम थी। लेकिन उपरोक्त सभी मामले, जिन पर श्री सरीन ने भरोसा किया है, उस अवधि से संबंधित हैं जब 1908 के अधिनियम संख्या 9 के प्रावधान लागू थे। नियम 4 को लेटर्स पेटेंट के खंड 27 के तहत इस न्यायालय को उपलब्ध नियम बनाने की शक्तियों के अनुसरण में बनाया गया था। लेकिन, तब वे शक्तियाँ लेटर्स पेटेंट के खंड 37 के तहत विधानमंडल की विधायी शक्ति के अधीन थीं। 1908 के अधिनियम संख्या 9 की पहली अनुसूची में अनुच्छेद 151 ने अपने मूल क्षेत्राधिकार के प्रयोग में उच्च न्यायालय द्वारा पारित डिक्री या आदेश से किसी भी अपील के लिए 20 दिनों की अवधि प्रदान की, जबकि नियम 4, उक्त अनुच्छेद 151 के विपरीत है। लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत अपील के लिए, एक अलग अवधि प्रदान की गई, यानी, अपील किए गए फैसले की तारीख से 30 दिन। उक्त नियम 4, इस न्यायालय द्वारा लेटर्स पेटेंट के खंड 27 के तहत उपलब्ध शक्तियों के तहत बनाया गया था, जिसे एक विशेष कानून का दर्जा प्राप्त था। इसलिए, विशेष कानून द्वारा निर्धारित 30 दिनों की अवधि को 1908 के अधिनियम संख्या 9 की धारा 29 की उप-धारा (2) द्वारा बचाया गया था, और वही पहले 1908 के अधिनियम क्रमांक 9 की अनुसूची में अनुच्छेद 151 द्वारा निर्धारित 20 दिनों की अवधि के विरुद्ध प्रचलित थी। दूसरे शब्दों में कहें तो 1 जनवरी, 1964 से पहले की अवधि के दौरान, जब अधिनियम सं. 1908 का 9 लागू था, अनुच्छेद 151 ने नियम 4 को रास्ता दिया और लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत अपील के लिए सीमा की अवधि अपील किए गए फैसले की तारीख से 30 दिन थी, जैसा कि उनके आधिपत्य भारत संघ बनाम राम कंवर[5] ,में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है। जब 1963 का अधिनियम संख्या 36 लागू हुआ, यानी 1 जनवरी 1964 को, इसके अनुच्छेद 117 ने 1908 के अधिनियम संख्या 9 के अनुच्छेद 151 को प्रतिस्थापित कर दिया। उक्त अनुच्छेद 117 किसी भी उच्च न्यायालय के डिक्री या आदेश से उसी न्यायालय में अपील के लिए 1908 के अधिनियम संख्या 9 के अनुच्छेद 151 द्वारा निर्धारित 20 दिनों के स्थान पर 30 दिनों का प्रावधान करता है , चाहे वह मूल क्षेत्राधिकार के प्रयोग में पारित किया गया हो या अपील न्यायिक क्षेत्र में। 1908 के अधिनियम संख्या 9 की धारा 5 स्वयं अन्य अधिनियमों के तहत निर्धारित समय के विस्तार पर लागू नहीं होती थी, लेकिन इसे उस पर लागू किया जा सकता था। इसका संचालन

---

[5] एआईआर 1962 एससी 247

नियम 4 तक नहीं बढ़ाया गया था। इसलिए, धारा 5उस नियम द्वारा निर्धारित समय को बढ़ाने के लिए आवेदन नहीं किया जा सका। हाथ में अपील 23 दिसंबर 1970 को प्रस्तुत की गई और 30 जनवरी 1971 को पुनः दाखिल की गई, अनुच्छेद 117 द्वारा शासित है। चूंकि 1963 के अधिनियम संख्या 36 के नियम 4 और अनुच्छेद 117 द्वारा अपील के लिए निर्धारित सीमा की अवधि समान है 1963 के अधिनियम संख्या 36 की धारा 29(2) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं और, इस प्रकार, नियम 4 की कोई बचत नहीं है और जहां तक सीमा की अवधि का संबंध है, इसे अनुच्छेद 117 को रास्ता देना होगा। यह इस प्रकार है कि 1963 के अधिनियम संख्या 36 का अनुच्छेद 117, न कि नियम 4, अब लेटर्स पेटेंट के तहत सभी अपीलों पर लागू होता है, और जहां तक देरी को माफ करने का सवाल है, सीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रावधान उस पर लागू होते हैं। अपील दाखिल करने का संबंध है। नियम 4 ने अकेले प्रवेश पीठ को समय से बाहर अपील दायर करने में दिखाए गए अच्छे कारण के लिए देरी को माफ करने का विवेक दिया है, लेकिन सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत इस तरह की देरी को माफ करने का अधिकार क्षेत्र अब अपील की सुनवाई करने वाली प्रत्येक पीठ के लिए उपलब्ध है, चाहे वह हो प्रस्ताव के चरण में या बाद की या अंतिम सुनवाई के चरण में। इसलिए, अपील की सुनवाई करने वाली पीठ 1 जनवरी, 1964 के बाद दायर अपील में सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत दिए गए आवेदन पर समय विस्तार देने या देने से इनकार करने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करने में सक्षम है। जनार्दन मिश्रा के मामले में सीजे मेहर सिंह ने विवाद के मुद्दे को पूरी तरह कवर किया। यह ध्यान रखना उचित है कि उस मामले में भी, अपील लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत थी और अपील किए गए फैसले की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद दायर की गई थी, यानी, उसी के लिए निर्धारित सीमा की अवधि। से, और उक्त अपील 1963 के अधिनियम संख्या 36 के लागू होने के बाद प्रस्तुत की गई थी। इसलिए, जनार्दन मिश्रा के मामले में दिया गया निर्णय उस बिंदु से प्रासंगिक है जो इस प्रश्न का विषय है, और कोई भी निर्णय विश्वसनीय नहीं है। श्री सरीन द्वारा किया गया विचार अब प्रासंगिक है, इस स्पष्ट कारण से कि वे सभी मामले उस अवधि से संबंधित हैं जब अधिनियम सं. 1908 का 9 लागू था और नियम 4 ने लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत अपील के लिए सीमा की एक अलग अवधि प्रदान की थी।

(5) इस प्रकार, इसका तात्पर्य यह है कि वास्तव में, जनार्दन मिश्रा के मामले (सुप्रा) में दर्ज निर्णय का अनुपात, और मातु राम और अन्य (सुप्रा) के मामले सहित विभिन्न निर्णयों का अनुपात,के बीच में कोई संघर्ष नहीं है जिस पर श्री सरीन ने भरोसा किया और ऊपर संदर्भित किया। इन सभी प्राधिकारियों को, जब एक साथ पढ़ा जाता है, तो बताते हैं कि यदि लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत अपील उस समय से बाहर दायर की गई थी जब 1908 का अधिनियम संख्या 9 लागू था, तो यह अकेले प्रवेश पीठ थी जो समय का विस्तार दे सकती थी, लेकिन यदि ऐसी कोई अपील 1963 के अधिनियम संख्या 36 के लागू होने के बाद, यानी 1 जनवरी 1964 को या उसके बाद दायर की गई थी, तो स्वीकार करने वाली पीठ अस्थायी रूप से देरी को माफ करने के सवाल पर विचार कर सकती है, लेकिन यह वह पीठ होगी जो सुनवाई करेगी। जो अंततः, सभी संबंधित पक्षों को सुनने के बाद, सीमा से परे अपील दायर करने के कारण की पर्याप्तता पर विचार करेगा और सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत देरी को माफ नहीं कर सकता है।

(6) उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, इस प्रश्न का मेरा उत्तर दो भागों में है, अर्थात्:

(ए) यदि नियम 4 लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत अपील पर लागू होता है, या, दूसरे शब्दों में, यदि 1908 का अधिनियम संख्या 9 लागू था जब उक्त अपील प्रस्तुत की गई थी, तो देरी को माफ करने का विवेक केवल स्वीकार करने वाली पीठ के लिए सीमित है, और बाद में अपील की सुनवाई करने वाली कोई भी पीठ अपील प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने में सक्षम नहीं होगी, अन्यथा समय से बाहर।

(बी) लेकिन यदि ऐसी अपील 1963 के अधिनियम संख्या 36 द्वारा शासित होती है, या, दूसरे शब्दों में, जब इसे 1 जनवरी 1964 को या उसके बाद प्रस्तुत किया गया है, तो अपील की सुनवाई करने वाली पीठ के पास देरी को माफ करने का अधिकार क्षेत्र है, इसे समय से परे दाखिल करने के लिए कारण की पर्याप्तता पर विचार करने के बाद। अपील स्वीकार करने वाली पीठ भी अपील स्वीकार करते समय उक्त देरी को माफ कर सकती है, लेकिन तब प्रतिवादी अपने प्रश्न को फिर से खोलने और अपील की सुनवाई करने वाली पीठ के समक्ष यह तर्क देने का हकदार होगा कि देरी को माफ करने के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं था। इसी तरह, यदि अपील स्वीकार करने वाली पीठ अपील

स्वीकार करते समय इस तरह की देरी को माफ करने से चूक जाती है, तो अपीलकर्ता अपील की सुनवाई कर रही पीठ से समय विस्तार का दावा कर सकता है, निश्चित रूप से समय के भीतर इसे दाखिल न करने के लिए पर्याप्त कारण दिखाकर।

प्रश्न संख्या 2

6. चाहे देरी को माफ करने की आवश्यकता वाला मामला उक्त नियम 4 के तहत हो या दोनों परिसीमा अधिनियमों में से किसी एक की धारा 5 के तहत, देरी को माफ करने वाली पीठ को यह दर्ज करना होगा कि देरी पर्याप्त और अच्छे कारण के कारण हुई थी। इस प्रकार, यह इस प्रकार है कि बेंच का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए कि दायर की गई अपील समय से बाधित थी और देरी की माफी वांछित या आवश्यक थी। इसके बाद बेंच देरी को माफ करने के लिए दिए गए कारणों पर अपना दिमाग लगाएगी और यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि देरी पर्याप्त और अच्छे कारण के कारण हुई थी, तो देरी को माफ किया जा सकता है, लेकिन बिना ध्यान दिए अपील को स्वीकार कर लिया जाएगा। पीठ को इस तथ्य से अवगत कराया जा रहा है कि उस पर समय की रोक लगी हुई है। मेरी राय में, देरी को माफ करने का कोई असर नहीं होगा। यह प्रतिवादी या उत्तरदाताओं के लिए परिसीमा की दलील उठाने के लिए खुला होगा और अपील की सुनवाई करने वाली पीठ उस आवेदन पर अपना निर्णय दर्ज करेगी। इसलिए, प्रश्न संख्या 2 का उत्तर नकारात्मक है।

प्रश्न संख्या 3

7. आदेश XLI, सिविल प्रक्रिया संहिता में निहित प्रावधान, डिक्री से पहली अपील को नियंत्रित करते हैं, लेकिन संहिता की धारा 117 के आधार पर, नियम 35 में निहित प्रावधान को छोड़कर, उक्त प्रावधान, खंड 10 पत्र पेटेंट के तहत अपील पर भी लागू होते हैं। संहिता की धारा 117 इन शर्तों में है:--

"इस भाग या भाग X या नियमों में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, इस संहिता के प्रावधान ऐसे उच्च न्यायालयों पर लागू होंगे।"

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि सिविल प्रक्रिया संहिता आम तौर पर उच्च न्यायालय पर लागू होती है, सिवाय इसके कि जब इसे विशेष रूप से बाहर रखा गया हो या जब तक कि उच्च न्यायालय ने स्वयं संहिता के किसी विशेष प्रावधान को खत्म करने वाले नियम नहीं बनाए हों। ऑर्डर एक्सएलआईएक्स, सिविल प्रक्रिया संहिता का नियम 3, जो संहिता के कुछ नियमों में निहित प्रावधानों के आवेदन को प्रतिबंधित करता है, यह प्रावधान करता है कि ऑर्डर एक्सएलआई का नियम 35 अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार के अभ्यास में उच्च न्यायालय पर लागू नहीं होगा। आदेश XLIX, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 117 और नियम 3 का संयुक्त प्रभाव यह है कि नियम 35 (डिक्री की तारीख और सामग्री से संबंधित) को छोड़कर आदेश XLI के प्रावधान लेटर्स पेटेंट के तहत अपील पर लागू होते हैं। सूबा सिंह कुरे सिंह बनाम नेकी किशन सहाय और अन्य[6], येलुमलाई और अन्य बनाम कुप्पम्मल और अन्य[7], श्रीमती आशो देवी बनाम दुखी साओ और अन्य[8], और लखपत सिंह और अन्य बनाम दल सिंह और अन्य[9] के रूप में दर्ज किए गए मामले, स्पष्ट रूप से इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि आदेश एक्सएलआई, सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम 1 के अनुसार अपील के ज्ञापन को तैयार करने पर आपत्ति प्रारंभिक चरण में ही ली जानी चाहिए, फिर भी उक्त संहिता के आदेश या किसी अन्य प्रावधान या उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों में ऐसा कुछ नहीं है, जो मोशन बेंच द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद आदेश एक्सएलआई, नियम 3, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत अपील के ज्ञापन को खारिज करने की शक्तियों के प्रयोग पर रोक लगाता है। इस प्रकार, उपरोक्त शक्ति का प्रयोग अपील की सुनवाई करने वाले न्यायालय द्वारा बाद के चरण में भी किया जा सकता है, अर्थात, प्रतिवादी/उत्तरदाताओं द्वारा ली गई आपत्ति पर। इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा मैम राज और अन्य बनाम

---

[6] ए.आई.आर.1957 पी.बी. 106

[7] ए. आइ. आर 1928 मद्रास 385

[8] ए. आई. आर 1965 पटना 472

[9] 1964 ए. अल. ज. 1049

दर्शन सिंह उर्फ रणजीत सिंह[10], पृष्ठ 247 में यह माना गया है कि यदि अपील स्वीकार कर ली गई है, तो आदेश XLI के 3 या किसी अन्य प्रावधान के तहत, समय-बाधित के रूप में ज्ञापन को किसी भी नियम के तहत खारिज नहीं किया जा सकता है। उक्त मामले पर चर्चा करते हुए, विद्वान न्यायाधीश ने चिंतापटला वेंकटनरसिन्हा रामचन्द्र राव और अन्य[11], और बिधु भूषण बख्शी बनाम कलाचंद रॉय[12] में दिए गए निर्णयों से समर्थन मांगा। उन दोनों मामलों में, अपील अभी तक स्वीकार नहीं की गई थी जब उसे अस्वीकार करने का प्रश्न उठा। चिंतापटला के मामले का अनुपात निर्णय यह है कि अपील का ज्ञापन, जो पंजीकृत नहीं किया गया है, को अपील के रूप में नहीं माना जा सकता है, बल्कि केवल न्यायालय में प्रस्तुत अपील के ज्ञापन के रूप में माना जा सकता है। जब तक इसमें खामियां हैं, तब तक न्यायालय केवल आदेश XLI, नियम 3, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत इसे वापस कर सकता है, ताकि अपीलकर्ता को इसे पूर्ण रूप में फिर से प्रस्तुत करने का मौका दिया जा सके। उक्त दोनों प्राधिकारियों में यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि किसी अपील को स्वीकार किए जाने के बाद उस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है जिस आधार पर इसे आदेश एक्सएलआई, नियम 3, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत खारिज किया जा सकता है। उस नियम के तहत किसी अपील को परिसीमा के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है और इसलिए, मम राज के मामले (सुप्रा) में विद्वान न्यायाधीश की टिप्पणी सही प्रतीत होती है, जहां तक यह समय-बाधित अपील की बात है। समय-बाधित अपील के स्वीकार होने के बाद, इसे समय-बाधित के रूप में खारिज कर दिया जाएगा, लेकिन उस स्कोर पर खारिज नहीं किया जाएगा। इसे स्पष्ट करने के लिए, मेरा मानना है कि एक अपील, स्वीकार किए जाने के बाद भी, उस आधार पर खारिज की जा सकती है जिस आधार पर इसे सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश एक्सएलआई, नियम 3 के तहत प्रवेश से पहले खारिज किया जा सकता है। यदि मैम राज के मामले (सुप्रा) में कोई भी अवलोकन इसके विपरीत है, तो उसे सही कानून बनाने वाला नहीं कहा जा सकता है। उपरोक्त चर्चा के आलोक में, इस प्रश्न का मेरा उत्तर सकारात्मक है।

---

[10] 1972 पी.एल.आर 241

[11] ए.आई. आर 1933 मद्रास 358

[12] ए. आई.आर 1927 कलकत्ता 775

प्रश्न संख्या 4

9. प्रक्रिया के नियम इस न्यायालय द्वारा नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 122 और 129 या लेटर्स पेटेंट के खंड 27 के तहत उपलब्ध नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाए गए हैं। इसलिए, उक्त नियमों में कानून का बल है। इसलिए, अपील दायर करने के लिए पूर्व शर्त या आवश्यक शर्त निर्धारित करने वाले इस न्यायालय द्वारा बनाए गए किसी भी नियम का अनुपालन न करने पर अपील के ज्ञापन को अस्वीकार कर दिया जाएगा। राम रछपाल बनाम रामजी दास[13] , 10 मई, 1967 को तय किए गए एक असूचित मामले में इस न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए फैसले का अनुपात भी ऐसा ही प्रतीत होता है। इसलिए, इस प्रश्न का मेरा उत्तर सकारात्मक है।

प्रश्न संख्या 5

10. यह प्रश्न प्रश्न संख्या 7 से जुड़ा हुआ है और इसलिए मैं उन पर एक साथ चर्चा करने का प्रस्ताव करता हूं। तदनुसार, इसे प्रश्न संख्या 7 को प्रश्न संख्या 6 के साथ निपटाया जाएगा।

प्रश्न संख्या 6

11. उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों का नियम 5 (1), ऊपर प्रस्तुत, उप रजिस्ट्रार को अपील के ज्ञापन को वापस करने के लिए अधिकृत करता है, जो संशोधन और रीफिलिंग के लिए आदेश XLI, नियम 3,नागरिक प्रक्रिया संहिता की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। एक समय के भीतर, जो उसके द्वारा तय किया जाएगा, एक समय में 10 दिनों से अधिक नहीं, वह उक्त अवधि को कुल मिलाकर 40 दिनों तक बढ़ा सकता है। इसलिए, यदि कोई अपील, जो मूल रूप से समय के भीतर दायर की गई थी, उप रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित समय के भीतर संशोधन और पुनः दाखिल करने के लिए वापस कर दी जाती है, और प्रारंभिक प्रस्तुति के 40 दिनों के भीतर दोबारा दाखिल करने पर उप रजिस्ट्रार द्वारा उस पर बिना किसी आपत्ति के विचार किया जाता है, हालांकि बाद में संशोधन और उसे पुनः दाखिल करने के लिए उसके द्वारा दी गई अवधि की समाप्ति पर, यह माना जाएगा

---

[13] 1962 के आरएफए नंबर 241

कि उप रजिस्ट्रार ने पहली बार में संशोधन और उसे पुनः दाखिल करने के लिए उसके द्वारा दिए गए समय को उस तारीख तक बढ़ा दिया है जब इस पर विचार किया गया था। उसके द्वारा, और मैं तदनुसार इस प्रश्न का उत्तर देता हूं।

प्रश्न संख्या 5 और 7

12. "अपील" और "अपील का ज्ञापन" दो अलग चीजें हैं। अपील एक निचली अदालत के फैसले की उच्च न्यायालय द्वारा की जाने वाली न्यायिक परीक्षा है। अपील के ज्ञापन में वे आधार शामिल हैं जिन पर न्यायिक परीक्षा आमंत्रित की जाती है। सिविल प्रक्रिया संहिता और इस न्यायालय द्वारा बनाए गए नियम अपील की प्रस्तुति से संबंधित मामलों के संबंध में प्रावधान करते हैं, जिसमें अपील का रूप, अपील के ज्ञापन की सामग्री और उसके साथ आने वाले दस्तावेज़ और अपील कैसे की जाती है, शामिल हैं और इसकी प्रस्तुति और स्वीकृति के बाद निपटाया जाएगा। उक्त प्रावधान या तो अनिवार्य या निर्देशिका हो सकते हैं। अपूर्ण अपील का अर्थ यह होगा कि इसमें कुछ निर्धारित विवरणों की कमी है। यदि कोई अपील दायर करते समय किसी नियम का अनुपालन नहीं करती है, जो अनिवार्य नहीं है, तो इसे अधूरा कहा जा सकता है, लेकिन जब यह किसी नियम का अनुपालन नहीं करती है, जो अनिवार्य है, तो इसे कोई अपील नहीं माना जाएगा। कानून की नजर. चूँकि लेटर्स पेटेंट अपील की कोई परिभाषा सिविल प्रक्रिया संहिता, लेटर्स पेटेंट या इस न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों में उपलब्ध नहीं है। अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री कौशल ने नागेंद्र नाथ डे बनाम सुरेश चंद्र डे[14] , पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि वर्तमान अपील, जब दिसंबर 23, 1970 को दायर की गई थी, नियम के अनुसार टाइप की गई प्रतियों के तीन सेट के बिना थी। नियमों के अध्याय 2-सी के 3 को उस दिन दायर की गई अपील के रूप में माना जाना चाहिए, यह नागेंद्र नाथ डे के मामले में उनके आधिपत्य द्वारा पृष्ठ 167 पर देखा गया है:

"सिविल पीसी में अपील की कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन उनके आधिपत्य में कोई संदेह नहीं है कि किसी पार्टी द्वारा अपीलीय अदालत में कोई भी आवेदन, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय के फैसले

[14] ए.आई.आर.1932 पी,सी, 165,

को रद्द करने या संशोधित करने के लिए कहा जाता है, सामान्य स्वीकृति के तहत एक अपील है शब्द का, और यह किसी अपील से कम नहीं है क्योंकि यह अनियमित या अक्षम है।"

13. उक्त मामले में अपील, जिसके खिलाफ आपत्ति की गई थी, अधीनस्थ न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ अपील नहीं होने और उस उद्देश्य के लिए अपर्याप्त मुद्रांकित होने के कारण अनियमित थी, और इसे अनियमितता के आधार पर और दोनों आधार पर खारिज कर दिया गया था। चूंकि नागेंद्र नाथ डे के मामले में यह बताने के लिए कुछ भी नहीं है कि उस मामले में अपील कानून के किसी भी अनिवार्य प्रावधान का उल्लंघन करके दायर की गई थी, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उस फैसले का अनुपात उस अपील पर लागू होगा जो उल्लंघन में दायर की गई है। ऊपर उल्लिखित नियम 3 में निहित प्रावधान, जो, जैसा कि वर्तमान में देखा जाएगा, प्रकृति में अनिवार्य है। नियमों के अध्याय 2-सी का नियम 2, जो ऊपर प्रस्तुत किया गया है, लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत अपील की पेपर-बुक की सामग्री से संबंधित है और उक्त अध्याय के नियम 3 में प्रावधान है कि उक्त अपील तीन के साथ होगी। (ए) अपील के ज्ञापन की टाइप की गई प्रतियां; (बी) जिस फैसले की अपील की गई है; और (सी) पेपर-बुक जो उस न्यायाधीश के समक्ष थी जिसके फैसले से अपील की गई है, और यह उप रजिस्ट्रार को निर्देश देता है कि यदि उक्त तीन टाइप की गई प्रतियां इसके साथ प्रदान नहीं की जाती हैं तो पत्र पेटेंट अपील प्राप्त न करें। ऑर्डर एक्सएलआई, सिविल पीसी के नियम 1 में भी ऐसा ही प्रावधान है कि अपील के ज्ञापन के साथ अपील की गई डिक्री की एक प्रति संलग्न की जाएगी। उक्त नियम की आवश्यकता है कि अपील के ज्ञापन के साथ डिक्री की प्रमाणित प्रति दाखिल की जानी चाहिए, इसे हमेशा अनिवार्य माना गया है, और जब अपील के ज्ञापन के साथ ऐसी प्रति नहीं होती है, तो यह वैध अपील नहीं है। नियमों के अध्याय 2-ए के नियम 9 में "प्राप्त करें" शब्द का उल्लेख मिलता है , जो इस प्रकार है:--

""प्रत्येक अपील में जिसमें इन नियमों के तहत एक रिकॉर्ड मुद्रित किया जाना है, अपीलकर्ता को अपनी अपील के साथ एक सौ रुपये की रसीद संलग्न करनी होगी जिसे रिकार्ड मुद्रण की लागत को कवर करने के लिए उच्च न्यायालय के कोषाध्यक्ष के पास जमा किया जाना चाहिए। किसी डिक्री की कोई भी प्रथम अपील तब तक प्राप्त नहीं की जाएगी जब तक कि उसके साथ ऐसी रसीद संलग्न न हो।"

14. उक्त नियम की व्याख्या करते समय, राम रछपाल के मामले (सुप्रा) में यह देखा गया कि नियम 9 प्रकृति में अनिवार्य है और यदि रसीद अपील के साथ संलग्न नहीं है, तो परिणाम यह होगा कि अपील नहीं की जाएगी, वास्तव में, इस न्यायालय में प्राप्त किया गया है। जय राम दास बनाम सोम प्रकाश और अन्य[15] में, इस न्यायालय द्वारा फिर से फैसला सुनाया गया कि उपरोक्त नियम 9 का अनुपालन करना होगा और इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। जब नियमों के अध्याय 2-सी के नियम 3 की भाषा को आदेश XLI, सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम 1 और उपरोक्त नियम 9 में निहित प्रावधान की भाषा के आलोक में पढ़ा जाता है, तो निष्कर्ष का विरोध करना मुश्किल है कि अध्याय 2-सी के उक्त नियम 3 में निहित प्रावधान अनिवार्य है और इसके उल्लंघन पर दंडात्मक परिणाम होंगे। इसलिए, यह स्पष्ट है कि जब लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत अपील दस्तावेजों की आवश्यक तीन प्रतियों के साथ नहीं होती है, तो यह अक्षम है और इसे इस न्यायालय में दायर या प्राप्त नहीं होने के रूप में माना जाना चाहिए और बाद में लौटा दिया गया। अपील को रजिस्ट्री द्वारा तब प्राप्त किया गया माना जाएगा जब इसे नियमों के अनुरूप सभी प्रकार से पूर्ण रूप से दायर या पुनः दाखिल किया जाता है, जिस पर रजिस्ट्री द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठाई जाती है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, अमृतसर बनाम महंत ईशर सिंह[16] में, सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति के लिए एक आवेदन सीमा की निर्धारित अवधि के भीतर 17 दिसंबर, 1970 को दायर किया गया था, लेकिन इसके आदेश XLV, नियम 3, सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार आदेश XLV, नियम 3, सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार अपील साथ नहीं किया गया था। इसलिए, अधिकारी ने उक्त दोष को इंगित करते हुए आपत्ति जताई और 18 दिसंबर, 1970 को अपील के आधार प्रदान करने के लिए उक्त आवेदन को 7 दिनों के भीतर फिर से दाखिल करने के निर्देश के साथ वापस कर दिया। उपरोक्त आपत्ति का अनुपालन करने के बाद 4 फरवरी 1971 को आवेदन पुनः दाखिल किया गया। सुनवाई की तारीख पर एक आपत्ति उठाई गई थी कि आवेदन समय से बाधित था क्योंकि उक्त आवेदन के लिए निर्धारित सीमा अवधि 60 दिन थी, जो 4 फरवरी 1971

---

[15] 1967 पाठ्यक्रम.एल.जे. 857, (17) 1972 पाठ्यक्रम। एल.जे.445.

[16] ए. आई. आर 1972 पुंज 389

को उस आवेदन को दोबारा दाखिल करने से बहुत पहले समाप्त हो गई थी। नियमों के अध्याय 8-ए का 1(ए) नियम का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार है: -

"सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति के लिए एक याचिका नागरिक प्रक्रिया संहिता के नियम 3 (1), आदेश XLV की आवश्यकताओं का अनुपालन करेगी..."

इस न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा यह माना गया था कि आदेश XLV, नियम 3 के प्रावधान अनिवार्य थे और चूंकि उक्त प्रावधानों का उल्लंघन था, क्योंकि जब आवेदन किया गया था तब अपील के आधार आवेदन के साथ दायर नहीं किए गए थे। 17 दिसंबर, 1970 को प्रस्तुत किया गया, कानून की नजर में यह कोई आवेदन नहीं था और इसलिए, उक्त आवेदन को 4 फरवरी, 1971 को दायर किया गया माना गया। उस दिन परिसीमा की अवधि, जैसा कि ऊपर बताया गया है, पहले ही समाप्त हो चुकी थी। और इसलिए, इसे समय से बाधित मानकर खारिज कर दिया गया।

15. उपरोक्त चर्चा से यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि लाइन लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत कोई अपील दस्तावेजों की टाइप की गई प्रतियों के तीन सेट दाखिल न करके नियमों के अध्याय 2-सी के नियम 3 के अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं करती है, इसे कानून की नजर में कोई अपील नहीं माना जाएगा और इसे उस दिन दायर नहीं माना जाएगा। इसे केवल उसी दिन दाखिल माना जाएगा जब यह नियमों के अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण हो जाएगा और रजिस्ट्री द्वारा पंजीकरण के लिए स्वीकार कर लिया जाएगा। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर इन शब्दों में दिया गया है।

16. प्रश्न संख्या 7 के पूर्वोक्त उत्तर को ध्यान में रखते हुए, इस निष्कर्ष से कोई बच नहीं सकता है कि एक लेटर्स पेटेंट अपील को उस दिन वैध और उचित रूप से दायर माना जाएगा जब इसे प्रतियों के तीन सेटों के साथ दायर किया जाएगा। नियम 3 में उल्लिखित दस्तावेज़। ऊपर उल्लिखित नियमों का अध्याय 2-सी । ऐसी अपील, यदि मूल रूप से समय के भीतर प्रस्तुत किए जाने पर दस्तावेजों की प्रतियों के उपरोक्त तीन सेटों के साथ नहीं आती है, तो इसे समय-बाधित के रूप में खारिज कर दिया जा सकता है यदि इसे दस्तावेजों की प्रतियों के उपरोक्त तीन सेटों के साथ फिर से दाखिल किया जाता है। इसके लिए निर्धारित सीमा अवधि की समाप्ति के बाद, जब तक कि सीमा

अधिनियम की धारा 5 या उपरोक्त नियम 4, जो भी लागू हो, के तहत देरी को माफ नहीं किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर तदनुसार दिया गया है।

17. उपरोक्त टिप्पणियों के आलोक में अंतिम निपटान के लिए परिशिष्ट अब डिवीजन बेंच के पास वापस जाएगा। वह बेनेह परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत देरी को माफ करने के आवेदन पर भी फैसला करेगा। इन परिस्थितियों में, इन कार्यवाहियों की लागत के बारे में कोई आदेश नहीं है।

आरएस नरूला, जे.

मैं सहमत हूं और मेरे पास जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है।

बल राज तुली, जे.

मैं भी सहमत हूं.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

स्मृति

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

कुरूक्षेत्र, हरियाणा